



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—जन-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, जनवार, अगस्त 10, 1985/शावण 19, 1907

No. 353]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1985/SRAVANA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह बलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कानूनी और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार
और सोक विकास तथा पेशन मंत्रालय
(कानूनी और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1985

अधिकृतना

सा. का. नि. 644 (अ) :—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपचारा (2) के अध्य (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए, निम्निचित नियम बनाती है, अधिकृत :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण (अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों के बीतन और भूते तथा सेवा की शर्त) नियम, 1985 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तरीके को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अनेकित न हो :—

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभियेत है;

(ब) "अधिकारण" से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण अभियेत है।

3. बीतन :—(1) अध्यक्ष तीन हजार पाँच सौ रुपए का बेतन और पाँच सौ रुपए का विशेष बेतन प्रतिमास प्राप्त करेगा; उपाध्यक्ष और सदस्य अधिकारण तीन हजार पाँच सौ रुपए प्रतिमास और तीन हजार रुपए प्रतिमास प्राप्त करेगा।

परम्परा किसी ऐसे अधिकारण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च स्थायालय के स्थायाधीक्ष के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या जो पेशन और/या उपदान, अधिकारी विविधनियि में नियोजक के अधिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति कायदे या अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति कायदे प्राप्त कर रहा है या काम छुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है सो पूर्वोक्त बेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेशन और उपदान के समतुल्य पेशन या अधिकारी विविधनियि में नियोजक के अधिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति कायदों, यदि कोई हों, की कुल रकम कम कर दी जाएगी।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :— अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य अपने बेतन के अनुकूल ऐसी दरों पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करते होंगे जो सीम हजार रुपये या उपर का बेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अणी "क" अधिकारियों को अनुज्ञा है।

5. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवा निवृत्ति : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या नदस्य जो अधिकरण में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था, अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति लेगा और किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसी अधीन न्यायाधीश की दफा में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अधिकरण में उसकी सेवा संविधान की दूसरी अनुमति के भाग "ब" के बैरा 11 (ब) (1) के अंतर्गत वास्तविक सेवा मानी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में यथा उपबंधित सेवा निवृत्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य :—

(1) उसको लागू सेवा निवृत्ति नियमों के अनुजार पेंशन और उपचान प्राप्त करने का हक्कार होगा।

(2) अपनी उपाधित छुट्टी अपनीत करने के लिए अनुशासत नहीं होगा किन्तु अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व उसको लागू नियमों के अनुजार छुट्टी सम्बलम् परिकोई हों के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हक्कार होगा।

6. छुट्टी : (1) अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई अधिकृत निम्नलिखित रूप में छुट्टी प्राप्त करने का हक्कार होगा :

(1) सेवा के प्रत्येक पूरे कवरेंजर वर्ष या उसी किसी भाग के लिए विशेष विमों की वर पर उपाधित छुट्टी;

(ii) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत शीस दिन की वर पर विकिला प्रमाणपत्र या विज्ञान काम के प्राधार पर प्राधार बेतन छुट्टी और आधा बेतन कुट्टी के लिए सम्बलम् उपाधित छुट्टी के द्वारा अनुबोय छुट्टी सम्बलम् के प्राधार के समतुल्य होगा;

(iii) सदस्य के विकेन्त्र नुसार प्राधार बेतन पर छुट्टी को पूरे बेतन गहित छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वह विकिलीय प्राधारों पर लो गई हो और सकाम विकिला प्राधिकारी के विकिला प्रमाणपत्र द्वारा समर्पित की गई हो;

(iv) पद की एक अवधि में एक सौ अस्ती विनों को अधिकरण कालावधि तक बेतन और भर्तों के बिना भासाधारण छुट्टी।

(2) परिव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण के साथ अपनी कार्य-संभालने के कारण पूर्ण प्रावकाश का उपभोग करने में असमर्थ है तो वह प्रावकाश को अनुपमुक्त कालावधि को छुट्टी के लिए में जोड़ने का हक्कार होगा।

सम्बलम्: इस उपनियम के प्रयोगम के लिए "प्रावकाश" से अधिकरण द्वारा याने जाने वाले प्रत्येक कलेक्टर वर्ष में तीस दिन का प्रावकाश अभिन्न है।

(3) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपाधित छुट्टी की बाबत छुट्टी सम्बलम् के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हक्कार होगा परन्तु इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन छुट्टी की मात्रा अधिकारी की नकद रकम प्राप्त की गई है एक सौ अस्ती विनों से अधिक नहीं होगी।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य अधिकरण में पदमुक्त होने की नारीय को पूर्व दरों पर उपनियम (2) के अधीन छुट्टी सम्बलम् पर यथा अनुबोय महाराई भर्तों प्राप्त करने का हक्कार होगा परन्तु वह ऐसी छुट्टी पर नगर प्रतिकर्त्ताम के भर्तों का या किसी अन्य भर्तों का हक्कार नहीं होगा।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी : उपाध्यक्ष और किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने के लिए सकाम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए राष्ट्रपति सकाम प्राधिकारी होगा।

8. पेंशन : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्ति प्रत्येक अधिकृत पेंशन का हक्कार होगा, परन्तु ऐसी पेंशन वेप महीं होगी ।

(i) यदि उसने दो वर्ष से कम सेवा की है; या
(ii) यदि उसे अधिकारियम की भारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटाया गया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष का उसके किसी भाग के लिए सात सौ रुपये प्रतिवर्ष की वर पर संगमित की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्ष की संभा पर व्याप्त लिए दिना पेंशन की अधिकतम रकम 3,500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु इस नियम के अधीन वेप पेंशन की कूल रकम ऐसी पेंशन (जिसके अंतर्गत संराजित वेंशन का भाग, यदि कोई है भी) की रकम सहित जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या जिसको प्राप्त करने के लिए हक्कार है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।

9. भविष्य निधि : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य साधारण भविष्य निधि में अपने विकाल पर अभिदाय करने का हक्कार होगा और उसके ऐसा विकाल होने की वशा में वह केसीय भविष्य निधि (केसीय सेवा) नियम के उपबंधों से जासित होगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अधिकल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह ऐसे नियमों से जासित होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व उसको साधू थ।

10. यात्रा भर्ते : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अधिकल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह ऐसे नियमों से जासित होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व उसको साधू थ।

11. छुट्टी यात्रा रियायत : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य उसी वर्षों और उन्हीं मापदानों और उन्हीं शर्तों पर जो 3000 रुपये या उससे ऊपर का बेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के बोर्डी "क" प्राधिकारी को जायू हैं, छुट्टी यात्रा रियायत का हक्कार होगा।

12. वास सुविधा : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक अधिकृत साधारण पूल वास सुविधा से लिली में पदस्थ भारत सरकार के सचिव की समाप्ति पर द्वारा दी या अधिकरण से उसकी वेतन पर द्वारा दी जाने के लिए की गई यात्रा भी है। यात्रा भर्तों, दैनिक भर्तों, व्यवसियत माल अवश्यक और अन्य समान चोरों के परिवहन के लिए उसी मापदान और दरों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भर्ते) नियम, 1956 में विहित है, हक्कार होगा।

(2) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल वास सुविधा उपलब्ध नहीं करती जाती है। या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसके बेतन के विवर अंतिम तक वर्ती पर अनुकूलि फीस के संबाय किए जाने पर उपयोग करने का हक्कार होगा।

(3) जहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुबोय अवधि के परे कालावधि निवास का अधिकारी नहीं करती जाती है। या वह यथारिति अतिरिक्त अनुकूलि फीस या शास्त्रीय कियाये का संबाय करने का दायी होगा और उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को लाभू नियमों के अनुसार बेतन कराया जा सकेगा।

13. सशारी सुविधा: भव्यक, उपाभ्यक या कोई सदस्य भारत सरकार के स्वाक्षर कार नियमों के प्रमुखार सरकारी और निजी प्रयोजनों के लिए की गई यात्राओं के लिए स्वाक्षर कार सुविधा का हक्कार होगा।

14. चिकित्सा: उपचार की सुविधाएँ: भव्यक, उपाभ्यक या अन्य सदस्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवा स्कॉम नियम, 1954 में यथा उपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हक्कार होगा और ऐसे स्थानों में बहुत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कॉम प्रबंदन में नहीं है, यहा भव्यक, उपाभ्यक और सदस्य केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परियार्थी नियमों में यथा उपबंधित सुविधाओं के हक्कार होगे।

15. भव्यक, उपाभ्यक के रूप में नियुक्ति उपच न्यायालय के आवीष्ट न्यायाधीशों की सेवा शर्तें: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी उच्च न्यायालय का कोई आवीष्ट न्यायाधीश भविकरण भव्यक या उपाभ्यक के रूप नियुक्त किया जाता है तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए नियमों में यथा अन्तर्विष्ट सेवा शर्तें उस पर लाग् होंगी।

16. अवधिकारी उपबंध: भव्यक, उपाभ्यक या अन्य सदस्य की सेवा को भर्ते इनके लिए इन नियमों में कोई अधिक्यकृत उपबंध उपलब्ध नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के संवित को उस सदस्य नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित की जाएगी।

17. नियमों को शिखिल करने की शक्ति: केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रबंदन के व्यक्तियों की बाबत शिखिल करने की शक्ति होगी।

[सं. ग-12018/1/85-ए. टी०]

प्रार. महादेवन, प्रबर. सुविध

MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, A.I.M.N.S. TRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 10th August, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 644 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);

(b) "Tribunal" means the Central Administrative Tribunal.

3. Pay: (1) The Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred plus a special pay of rupees five hundred per mensem; a Vice Chairman and a Member shall receive a pay of rupees three thousand five hundred per mensem and rupees three thousand per mensem, respectively:

Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under

the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance: The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Grade 'A' Officers of the Central Government drawing a pay of rupees three thousand or above.

5. Retirement from parent service on appointment as Member: (1) The Chairman, a Vice-Chairman or a Member who, on the date of his appointment to the Tribunal, was in service under the Central Government or a State Government, shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal and in the case of a sitting Judge of a High Court who is appointed as Chairman, a Vice-Chairman, his service in the Tribunal shall be treated as Actual service within the meaning of para 11 (b) (i) of Part 'D' of the Second Schedule to the Constitution.

(2) On such retirement as is provided for in sub-rule (1), the Chairman, Vice-Chairman and Member:

- (i) shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the retirement rules applicable to him;
- (ii) shall not be allowed to carry forward his earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.

6. Leave: (1) A person, on appointment in the Tribunal as a Chairman, Vice-Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows:

- (i) earned leave at the rate of fifteen days for every completed calendar year of service or a part thereof
- (ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;
- (iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the Member, provided it is taken on Medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority
- (iv) extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.

(2) If the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule "vacation" means vacation of thirty days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, the Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and sub-rule (2) of rule 5 shall not exceed 180 days.

(4) The Chairman, the Vice-Chairman or other Members shall be entitled to receive the dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (2) at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal;

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance or any other allowance on such leave.

7. Leave sanctioning authority: The Chairman shall be the authority competent to sanctioning leave to the Vice-Chairman and a Member and the President shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

8. Pension: (1) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to pension provided that no such pension shall be payable:

- (i) if he has put in less than two years of service; or
- (ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub section (2) of section 9 of the Act.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum:

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, (if any) drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court.

9. Provident Fund: The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the Central Provident Fund (Central Services) Rules:

Provided that if the Chairman, a Vice-Chairman or a Member was Judge of a High Court or was a Member of an *All India Service* immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.

10. Travelling Allowances: The Chairman, a Vice-Chairman or other Member while on tour as on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956.

11. Leave Travel Concession: The Chairman, a Vice Chairman or other Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to Grade 'A' Officer of the

Central Government drawing a pay of rupees three thousand or above.

12. Accommodation: (1) Every person appointed to the Tribunal as a Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the use of an official residence from the general pool accommodation of the type admissible to an officer of the rank of a Secretary to the Government of India stationed at Delhi on the payment of the licence fee at the rates prescribed by the Central Government from time to time.

(2) When a Chairman, a Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1) he may be paid every month an allowance of an amount equal to fifteen percent of his pay.

(3) Where the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules applicable to Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.

13. Facility of conveyance: The Chairman, Vice Chairman and a Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the Staff Car Rules of the Government of India.

14. Facilities for Medical Treatment: The Chairman, Vice-Chairman or other Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Service Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the Chairman, Vice-Chairman and members shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules.

15. Conditions of service of sitting Judges of the High Court appointed as Chairman or Vice-Chairman: Notwithstanding anything contained in these rules, where a sitting judge of a High Court is appointed as the Chairman or a Vice-Chairman of the Tribunal the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder shall apply to him.

16. Residuary provision: The Conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman or other Member for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India belonging to the Indian Administrative Service.

17. Powers to relax rules: The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. A-12018/1/85-AT]
R. MAHADEVEN, Under Secy.